POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मार्च, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2018-19 का बजट रखा। बजट में कई घोषणाओं का ताना-बाना बुनकर सभी को खुश करने का प्रयास किया गया है। बजट पर चुनावी छाया साफ नजर आ रही है।

खासकर, किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज को माफ करने व खेती की सेहत सुधारने की घोषणा कर किसानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाओं का विस्तार करने का सपना भी संजोया गया है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और बुनियादी जरूरतों को अहमियत देकर बजट को संवारा गया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी लोकसभा में 2018-19 का आम बजट प्रस्तुत किया। बजट में खेती और किसान, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन को खास प्राथमिकता दी गई है। गांवों के गरीब व मध्यम वर्ग को फिर से घर का सपना दिखाया गया है। हेल्थ केयर बीमा योजना लागू कर गरीबों को राहत देने की घोषणा स्वागत योग्य है। सामाजिक कल्याण को अहमियत देने तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का भी वादा बजट में शामिल है। भ्रष्टाचार व कालेधन के प्रवाह पर रोक लगाने के प्रयासों को जारी रखने की बात फिर से दुहराई गई है। बजट में कई सुधार भी सामने आए हैं, जो देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने और बहुआयामी विकास को नई दिशा देंगे।

कुल मिलाकर दोनों बजट तभी अच्छे कहे जा सकेंगे, जब घोषणाएं वास्तविक रूप से धरातल पर उतरें और उनका समय पर सही क्रियान्वयन हो। इसके लिए समय का निर्धारण और प्रशासनिक सुधार बेहद जरूरी है। नहीं तो ये बजट भी पुरानी कई घोषणाओं व योजनाओं की तरह कागजी पुलिन्दा बन कर रह जाएंगे। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रख सकें और लाभान्वित हो सकें।

वरिष्ठ नागरिकों को मिली राहत

केन्द्रीय बजट में इस बार मध्यम वर्ग को आयकर में कोई राहत नहीं मिल पाई है। वित्त मंत्री का कहना है कि उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में राहत दी जा चुकी थी। वेतनभोगी कर्मचारियों को 40 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस की 34200 रुपए की छूट वापस ले ली है। शिक्षा व स्वास्थ्य सेस को 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया गया है।

आयकर में वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई हैं। उनकी जमा योजनाओं पर मिली ब्याज की आय पर कर छूट की सीमा पांच गुना बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी है। उन्हें आयकर की धारा 80डी और 80डीडीबी के तहत मिलने वाली कटौती सीमा को भी बढ़ाकर लाभान्वित किया गया है।

राजस्थान के बजट में 80 साल से अधिक के बुजुर्ग के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा की शुरुआत की गई है। साथ ही उनके साथ एक अटेंडेंट का भी आधा किराया लगेगा।

महिला व बाल विकास पर एक नजर

केन्द्रीय बजट में 8 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। पहले साल यह लक्ष्य 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का था। इस बार लक्ष्य बढ़ाया गया है।

राजस्थान के बजट में आंगनबाड़ी महिला कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मानदेय कर्मियों के कल्याण के लिए सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम भी अब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ग्रामीण बालिका और महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी पैड का वितरण होगा। महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में 18 साल से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 2 साल की चाइल्ड केयर अवकाश का प्रस्ताव रखा गया है।

स्वयंसेवी महिला संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई प्रावधान बजट में है। भामाशाह योजना के तहत 'सुरक्षा कवच' प्रदान करने का वादा किया गया है। मिड-डे-मील में अब हफ्ते में तीन बार बच्चों को दूध भी पिलाया जाएगा।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2017

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 36 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2017 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2017 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2018 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा

केन्द्रीय बजट में किसानों व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने कृषि ऋण के लक्ष्य को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। धान जैसी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की लागत से 50 प्रतिशत ऊपर तय करने की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा है कि सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने पर है। रबी की फसलों के लिए एमएसपी में पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार कृषि जिंसों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएगी।

राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लघु और सीमांत किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐसे किसानों के 30 सितंबर 2017 तक बकाया अल्पकालिक फसली ऋण में से 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इससे सरकार पर करीब 8 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार ने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का भी गठन किया है जो स्थाई संस्थान के रूप में काम करेगा।

किसानों को फसल उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर लाभ पहुंचाया जा रहा है। भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए गोदाम बनाने पर 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ष 2018-19 से किसानों का भूमि पर लगने वाला लगान माफ किया जाएगा। इसके अलावा भी किसानों को बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

युवाओं को दिया रोजगार का भरोसा

केन्द्रीय बजट में रोजगार सृजन के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 70 लाख नौकरियों की घोषणा कर उन्हें सुनहरा सपना दिखाया है। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को अधिक रोजगार देने की बात भी की गई है।

स्वरोजगार के लिए कौशल विकास व प्रशिक्षण पर जोर देने और मुद्रा योजना के तहत ऋण देने की घोषणा बजट में है। इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। लघु और मध्यम उद्यम के जरिए रोजगार बढ़ाने के लिए बजट में 3794 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिसंबर से पहले 1 लाख 8 हजार नौकरियां देने का ऐलान किया है। कमजोर व सामान्य वर्ग के 50 हजार परिवारों को सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी स्वरोजगार योजना के तहत बिना कुछ गिरवी रखे 4 फीसदी ब्याज पर 50 हजार रुपए का ऋण खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दिया जाएगा।

साथ ही भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत एससी/एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के 50 हजार परिवारों को भी यह सुविधा मिलेगी। बेरोजगारों को नियमित प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।

ग्रामीण विकास पर ज्यादा ध्यान

केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जाल बिछेगा। गांवों की सड़कों को कृषि बाजारों से जोड़ा जाएगा। 22 हजार हॉज कृषि बाजार बनेंगे। आजीविका मिशन के लिए 1366 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चार करोड़ गरीबों के घर 'सौभाग्य' योजना के तहत रोशन होंगे। इसके लिए 2750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए 3800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 27506 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में जानकारी दी है कि प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 52 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 766 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ा जाएगा।

जनवरी 2012 तक के लंबित 2 लाख कृषि कनेक्शन आगामी वर्ष में दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा भी बजट में ग्रामीण विकास को पंख लगाने के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई है।

हेल्थ केयर से सुधरेगी गरीब की सेहत

केन्द्र सरकार के बजट में गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हेल्थ केयर बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इसे देश के इतिहास में पहली और दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताया जा रहा है। कहा गया है कि 50 करोड़ जरुरतमंद परिवार इस योजना का फायदा ले सकेंगे। मेडिकल बीमा के तहत ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यदि यह योजना सही रूप से लागू होती है, तो यह ऐसे परिवारों के लिए बेहद लाभदायक होगी।

राजस्थान के बजट में राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में नई कैथ लेब व जयपुरिया अस्पताल में स्वाइन फ्लू लैब की स्थापना होगी। राज्य में 28 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे तथा 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तब्दील किया जाएगा। धौलपुर में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। निजी क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी। मातृ एवं शिशु इकाइयों में 18 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन सिस्टम स्थापित होंगे। चिकित्सकों, नर्सों व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नई भर्ती भी की जाएगी।

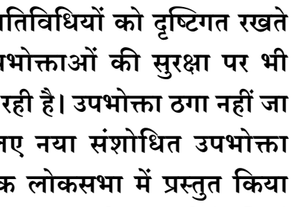

'सुरक्षित हो डिजिटल बाजार व्यवस्था'

उपभोक्ताओं के वैश्विक संगठन 'कन्ज्यूमर इंटरनेशनल' ने इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस-15 मार्च के अवसर पर पूरे विश्व में डिजिटल बाजार व्यवस्था को उपभोक्ताओं के हक में सुरक्षित, न्यायोचित और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए 'ई-कॉमर्स' विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।

पिछले कुछ सालों से 'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार की एक खास पहल रही है। ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उपभोक्ता ठगा नहीं जा सके इसके लिए नया संशोधित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अभी तक ई-कॉमर्स कंपनियां जो कि कानून के दायरे से बाहर थीं, को भी उपभोक्ता अथॉरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। जिससे कि कानून के अन्तर्गत उन पर कड़ा शिकंजा कसा जा सके।

प्रदेश की उपभोक्ता संस्थाएं भी इस अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर